

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीगराना(कोटपूतली-बहरोड)  
पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद संख्या  
321/2020

रजू दिनांक  
29.12.2020

निर्णय दिनांक  
28.05.2024

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नीगराना जिला अलवर हाल जिला

वादी

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र रामानन्द जाति अहीर निवासी ग्राम माजरी कलां तह0 नीगराना।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

पैरोकार सरकार - वादी

श्री राजेन्द्रसिंह- प्रतिवादी स्वयं

-:निर्णय:-

दिनांक :- 28.05.2024

आज यह पत्रावली सुनाये जाने निर्णय आदेश पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित आए।  
वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख.नं. 1460/1988/0.26 हैक्टैयर किरम  
नीगराना राजस्व ग्राम माजरीकलां तह0नीगराना मे स्थित होकर उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ है  
वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी संवत 2073-76) मे प्रतिवादी के नाम से दर्ज है, जिसकी  
नितम प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। पटवारी हल्का माजरीकलां द्वारा दिनांक 23.09.2020  
इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उक्त वर्णित ख.नं. 1460/1988/0.26 हैक्टैयर मे  
0.26 हैक्टैयर भूमि पर प्लाटिंग कर उक्त भूमि को अकृषि के उपयोग मे ली जा रही है जिस  
प्रतिवादी ने कृषि भूमि को संपरिवर्तन का कोई समक्ष आदेश प्राप्त नहीं कर रखा है तथा  
उक्त पर यह कृषि भूमि अब पुनः कृषि करने योग्य नहीं है। पटवारी रिपोर्ट एवं नकल नक्शा  
संलग्न है। राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि मे कृषि करने का ही  
धिकार प्रदान किया गया है जबकि प्रतिवादी द्वारा उक्त कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन बिना  
अधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई  
प्रतिवादी के इस कृत्य की देखा देखी मे अन्य लोगों द्वारा भी इसी प्रकार कृषि भूमि का  
रूप खराब किया जा सकता है जिससे भविष्य मे कृषि संबंधी उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा  
यही अवैध कॉलोनियों की स्थापना हो जायेगी जो भविष्य मे क्षेत्र के विकास मे बाधक  
आदि आदि अंकित करते हुए वादपत्र अंतर्गत धारा 177 राज0काश्त0अधिनियम 1955  
प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी के 1460/1988/0.26 हैक्टैयर वाके ग्राम माजरीकलां तह0  
नीगराना मे से 0.26 हैक्टैयर रकबे पर बिना किरम परिवर्तन आदेश के अवैध प्लाटिंग की हुई  
इसलिए उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर  
वादी विधिवत तलबी हाजिर अदालत आया एवं अपना जवाब दावा पेश किया गया।  
जवाब दावा दिलाई गई। मुताबिक प्रस्तुत जवाब दावा का सारतः रहा कि जिम्मन नं. 1  
जो ख.नं. एवं विवादित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ के बाबत होकर स्वीकार है एवं वाद  
जिम्मन नं. 4 आंशिक रूप से स्वीकार है अंकित करते हुए हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 23.  
2020 को पेश की गई रिपोर्ट खिलाफ गौका गलत पेश की गई है उक्त आराजी के कुल  
रकबे मे से मात्र 20एयर रकबा पर ही लघु उद्योग का निर्माण किया हुआ है तथा शेष हिस्सा  
कृषि हेतु ही उपयोग उपभोग मे लिया जा रहा है तथा वर्तमान मे भी शेष हिस्सा काश्त हेतु  
उपयोग मे लिया जा रहा है। दिनांक 07.02.2001 को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक मे

नये महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कारखानों को इस हेतु प्रोत्साहित करने हेतु उनकी स्वयं की भूमि में से 1000 वर्गमीटर भूमि को उपयोग करने पर स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसे उद्योग लगाने के लिए कृषि से अकृषि कार्य के लिए किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी उक्त निर्णय के संदर्भ में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर के पत्र क्रमांक / ए.डी.एम.(प्रथम) / पी.ए. / 2001 / 551 दिनांक 05.03.2001 की प्रति संलग्न है तथा उक्त निर्णय के बाद माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प-6(5) राज-6 / 2001 / 32 जयपुर दिनांक 28.05.2002 द्वारा एक आदेश जारी किया कि राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए नियम 199 के नियम 5क में की अगिव्यक्ति 1000 वर्गमीटर के स्थान पर अधिकतम 2500 वर्गमीटर प्रतिस्थापित की जावेगी। इसलिए मिन प्रतिवादी द्वारा उक्त आदेशों के अनुपालना में ही अपनी उक्त आराजी में कुछ हिस्से पर ही लघु उद्योग लगाया हुआ है - आदि अंकित करते हुए प्रतिवादी का जवाब स्वीकार किया जाकर वादी के वादपत्र में हर्जा-खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

वादी ने अपने वाद पत्र की तारीख में पटवारी हल्का माजरीकलां द्वारा मौका जाच वाके ग्राम माजरीकलां दिनांक 23.09.2020 पेश किया जो शामिल पत्रावली है एवं वाद पत्र दिये जाने उपरान्त कोई मौखिक साक्ष्य स्वरूप वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा की तारीख में दर्तावेजात स्वरूप राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प0 9(78)राज'6 / 2007 / 12 जयपुर दिनांक 03.10.2017 एवं कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर के पत्र क्रमांक / ए.डी.एम.(प्रथम) / पी.ए. / 2001 / 551 दिनांक 05.03.2001 की प्रति, उक्त निर्णय के बाद माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प-6(5) राज-6 / 2001 / 32 जयपुर दिनांक 28.05.2002 की छायाप्रतियां पेश की गईं संलग्न पत्रावली है।

उत्तरपक्षकारान की प्रकरण के वादत वहस सुनी गई। दौराने वहस वादी / पैरोकार द्वारा वाद पत्र के जिम्गनों को दोहराते हुए मुताबिक पटवारी हल्का माजरी कलां की जाच रिपोर्ट वाके ग्राम माजरीकलां दिनांक 23.09.2020 के विवादित आराजी के रकबा हैक्टेयर पर बिना किसम परिवर्तन आदेश के भूमि पर प्लाटिंग कर भूमि का अकृषि प्रयोजन में लिये जाने की स्थिति में वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाकर उक्त भूमि अकृषि भूमि / सिवायचक घोषित किये जाने का अभिकथन किया।

ठीक इसी प्रकार प्रतिवादी ने वादी के वादपत्र के जिम्गनों को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा के जिम्गनों को दोहराते हुए दौराने वहस अभिकथन किया कि उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है तथा वादी ने अपने वादपत्र में उक्त विवादित भूमि के संपूर्ण रकबा 0.26 हैक्टेयर पर प्लाटिंग कर अकृषि के उपयोग में मुताबिक पटवारी माजरी कलां की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.09.2020 के अनुसार ही प्रकरण प्रस्तुत किया अपने वादपत्र में अंकित किया है जबकि वादी द्वारा प्राप्त पटवारी हल्का माजरी कलां में प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार हल्का पटवारी ने विवादित आराजीयात 0.26 हैक्टेयर कुल पत्थर फ़ैक्ट्री का निर्माण कर वाणिज्यिक / औद्योगिक प्रयोजन के रूप में बिना पत्र क्रमांक प-6(5) राज-6 / 2001 / 32 जयपुर दिनांक 28.05.2002 के आदेशों के पालन कराये मौके पर राजेन्द्र सिंह पुत्र रामानन्द जाति अहीर निवासी माजरी कलां द्वारा किया जाना अंकित कर पेश किया है इस प्रकार से मौके रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं वादपत्र दोनों ही अपने आप में विरोधाभाषी है जबकि मुझ जवाब प्रस्तुतकर्ता / प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी में से मात्र 0.20 हैक्टेयर रकबा पर ही लघु उद्योग का निर्माण किया है तथा शेष हिस्सा कृषि हेतु उपयोग उपयोग में लिया जा रहा है तथा लघु उद्योग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प0 9 (78) राज6 / 2007 / 12 जयपुर दिनांक 03.10.2017 के अनुसार संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 6 में यह प्रावधान है कि इन नियमों के अंतर्गत किसी बात के होने पर भी, संपरिवर्तन के लिए कोई भी अनुज्ञा वहां अपेक्षित नहीं है। कोई खातेदार अगिधारी अपनी खातेदारी भूमि पर 01 एकड़ से अनधिक क्षेत्र पर लघु उद्योग इकाई, कजावा (छोटा ईट-भट्टा) की स्थापना करना चाहता है अथवा कृषि सुविधा या लोकोपयोगी प्रयोजन हेतु उपयोग करना चाहता है इस प्रकार उक्त भूमि उसकी खातेदारी में बनी रहेगी आदि - आदि का अंकन किया हुआ है

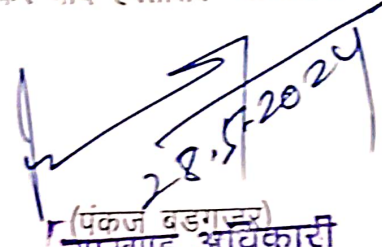
जिला मजिस्ट्रेट की छायाप्रति संलग्न है एवं कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर के पत्र क्रमांक/ ए.डी.एम.(प्रथम)/पी.ए./2001/551 दिनांक 05.03.2001 की प्रति, उक्त निर्णय के वाद माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प-6(5) राज-6/2001/32 जयपुर दिनांक 28.05.2002 की छायाप्रतियां भी पेश की है जो शामिल पत्रावली है जिसके मुताबिक नौ ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग को बढ़ावा एवं कारखानों को इस लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उपयोग करने पर रूपांतरण की आवश्यकता नहीं होगी तथा ऐसे उद्योग लगाने के लिए भी अकृषि कार्य के लिए किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। अदि-आदि का अभिकथन करते हुए प्रस्तुत नजीरात के आधार पर मुझ उत्तरदाता / प्रतिवादी का जवाब स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उक्त पक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत उत्तरदाता के गहनता से अवलोकन उपरांत प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीरात राजस्थान सरकार के निर्णय क्रमांक प0 9 (78) राज-6/2007/12 जयपुर दिनांक 03.10.2017 एवं जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर के पत्र क्रमांक/ ए.डी.एम.(प्रथम)/पी.ए./2001/551 दिनांक 05.03.2001 तथा माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प-6(5) राज-6/2001/32 जयपुर दिनांक 28.05.2002 की प्राप्त छायाप्रतिया उक्त तीनों की नजीरात वादी के जवाब वादों के वादत पूर्ण रूप से बक्ष्या पाई जाने की स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा वाद को सुसंगत ढंग से साबित नहीं कर पाने की स्थिति में यह न्यायालय वादी के वाद को अस्वीकार योग्य पाता है।

**आदेश**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा वाद पूर्णरूप से साबित नहीं किये जाने की स्थिति में अस्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी का हाल आराजी ख.नं. 1460/1988/026 पर किरम बरानी राजस्थ ग्राम माजरीकला तह0नीमराना के वादत के वाद को खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिट्ठी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(पंकज बडगप्पूर)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमराना (कोटपतली-बहरोड़)  
जिला कोटपतली-बहरोड़(राज0)

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली-बहरोड)  
पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद संख्या  
321/2020

रजू दिनांक  
29.12.2020

पर्चा डिक्री दिनांक  
28.05.2024

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहरीलदार, नीमराना जिला अलवर हाल जिला  
कोटपूतली-बहरोड।

बनाम

वादी

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र रामानन्द जाति अहीर निवासी ग्राम माजरी कलां तह0 नीमराना।

दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रतिवादी

—:पर्चा डिक्री:—

वादी की ओर से पैरोकार सरकार व प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.05.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा वाद पूर्णरूप से साबित नहीं किये जाने की स्थिति में अरवीकार योग्य पाये जाने पर वादी का आराजी ख.नं. 1460/1988/0.26 हैक्टैयर किस्म बरानी राजस्व ग्राम माजरीकलां तह0नीमराना के बाबत के वाद को खारीज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बंद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज बडगूजर)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमराना(कोटपूतली-बहरोड)  
जिला कोटपूतली-बहरोड(राज0)